



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 98/12

निर्णय दिनांक: 01.05.2018

1. श्रवणराम पुत्र बहादुरराम जाति नायक निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खान्जुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 26-10-1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री नारायणदास खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 26-10-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

खाजुवाला के चक 113 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 59/32 व 59/39 में 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ।

अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह साधारण नोटिस है अथवा रजिस्टर्ड नोटिस कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। साधारण नोटिस है तो उस पर कोई तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट नहीं है। अदालत मातहत की फर्द अहकाम में कहीं भी रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। बिना आदेश यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाते हैं तो ऐसे नोटिस की कानून में कोई अहमियत नहीं है। यदि रजिस्टर्ड नोटिस मान भी लिया जावे तो उसकी रसीद या एडी पत्रावली में कहीं उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। सुनवाई का अवसर प्रदान न देकर अदालत मातहत ने नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिलिखित व सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विशेष आवंटन के लिए बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थना पत्र एकपक्षीय खारिज किया गया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, आदेश अधिनस्थ न्यायालय का सेट असाईड किया गया।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-10-1999 के विरुद्ध अपील 13-06-2012 को पेश की है। जो करीब 13 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-10-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 13-06-2012 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 13 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 59/32 व 59/39 में 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि की बकाया राशि जमा कराने हेतु व बकाया सबूत पेश करने हेतु नोटिस क्रमांक 20367 दिनांक 11-10-1999 जारी किये गये

कि वे वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि व मय ब्याज जमा करावें अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। अपीलांट द्वारा निर्धारित तिथि को ना तो स्वयं उपस्थित आया व ना ही आवंटन हेतु बकाया राशि मय ब्याज जमा करवाई है। आवंटन हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई ना ही वांछित सबूत प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन दिनांक 26-10-1999 को निरस्त कर दिया गया।

(3) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित बकाया राशि मय ब्याज जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा बकाया राशि जमा नहीं किये जाने के कारण से आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 26-10-1999 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर